20 जुलाई 2018

मैक्सिको राष्ट्रपति चुनाव 2018

*डॉ.स्तुति बनर्जी**

नेशनल रीजनरेशन मूवमेंट (मोरेना) पार्टी के श्री अंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको के अगले राष्ट्रपति होंगे।[i] उन्होंने 53.19 प्रतिशत मत पाकर चुनाव जीत लिया है। वे 1 दिसंबर को सत्ता संभालेंगे। नई मैक्सिको कांग्रेस 1 सितंबर को सत्ता में आएगी। मोरेना ने सीनेट और चैंबर ऑफ डिप्यूटीज में भी बहुमत प्राप्त किया है। 1997 के बाद यह पहला अवसर है, जब किसी प्रत्याशी को दोनों चैंबर्स में जीत मिली हो। राष्ट्रपति के लिए चुने गए लोपेज ओब्राडोर 53 फीसदी मत पाकर चुनाव जीते हैं। मतदाता चाहते थे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हो और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए। क्योंकि हत्याओं की दर काफी बढ़ गई है। चुनाव स्वयं ही कई हत्याओं का प्रत्यक्षदर्शी बना। करीब 50 उम्मीदवारों की हत्याएं हुईं, कुछ जगहों पर हमले हुए और यहां तक कि पत्रकारों को भी धमकियां दी गईं।

चुनाव को लोकतंत्र की जीत और बदलाव के लिए मतदान हेतु लोगों की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति पद हेतु चुने गए लोपेज अब्राडोर पिछले दो बार चुनाव जीतने में असफल रहे थे। लेकिन इस बार वही लोगों की पसंद साबित हुए। नए राष्ट्रपति दक्षिण-पूर्व राज्य टबास्को के एक दुकानदार के पुत्र हैं। उन्होंने अपने राजनैतिक सफर का आरम्भ 1970 में किया था। उस समय वह इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी (पीआरआई) में शामिल थे। बाद में उन्होंने कुछ दूसरे राजनैतिक असंतुष्टों के साथ मिलकर पार्टी ऑफ द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन (पीआरडी) की स्थापना में योगदान दिया था। 2000 में वे मैक्सिको शहर के मेयर चुने गए। इसके बाद 2006 और 2012 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े और दोनों ही बार हारे।

घरेलू मुद्दे (एजेंडा)

नए राष्ट्रपति के सामने व्यापक घरेलू मुद्दे (एजेंडा) हैं और उन्हीं पर मुख्य रूप से उनका ध्यान है। उन्होंने चुनाव में गरीबी कम करने का वादा किया था और ऐसा समझा जाता है कि अपने इसी अभियान में वह दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं।

नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर का चुनावी मुद्दा मुख्य रूप से भ्रष्टाचार समाप्त करना और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना था। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार और कामकाज में पारदर्शिता का न होना राष्ट्रपति चुनाव में पीआरआई की हार का मुख्य कारण है। भ्रष्टाचार के घोटालों ने चुनाव अभियान के दौरान पीआरआई की साख को क्षति पहुंचाई। अब यह देखना है कि नए राष्ट्रपति इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाते हैं। उन्होंने कहा था कि वह सरकारी खर्चों और सरकारी सुविधाओं में कटौती करना चाहेंगे। वह राष्ट्रपति का विमान बेचेंगे, अपनी तनख्वाह आधी कर देंगे तथा राष्ट्रपति भवन के बजाय अपने छोटे घर में रहेंगे। उन्होंने कहा था कि वे मैक्सिको नौसेना के लिए अमेरिकी सरकार से लंबित आठ सशस्त्र लॉकहीड मार्टिन एमएच-60आर हेलीकाप्टरों की खरीद रद्द करेंगे, क्योंकि मैक्सिको उनका खर्च वहन नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि इससे राजनैतिक अभिजात्यों की जीवन शैली बदलेगी। पुराने ढंग से कार्य करने के जिन तरीकों की नए राष्ट्रपति ने निंदा की थी और उसे भ्रष्ट बताया था, उन्हें बारीकी से देखी जाएगी और उजागर किया जाएगा। गरीबों पर और विशेषकर देश के दक्षिणी हिस्से में अनियंत्रित हो चुकी गरीबी पर ध्यान होगा।ii फिर भी नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर इसे दूर करने के लिए कैसी नीतियां अपनाएंगे तथा चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को किस तरह पूरा करेंगे, इसका विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

नई सरकार से उम्मीदें ज्यादा होंगी। उसे भ्रष्टाचार-निरोधी समितियों के गठन के लिए ऐसे समर्थन की आवश्यकता होगी जिसमें कांग्रेस की अन्य पार्टियों का हस्तक्षेप न हो। ऐसी समितियों की स्वतंत्रता, उनकी क्रियान्वयन शक्ति और राष्ट्रपति की नीतियों को लागू करने पर अभी प्रश्न बना हुआ है। नए राष्ट्रपति के नियंत्रण में भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के लिए विपक्ष के विरोध तथा राजनैतिक संस्थानों वातावरण से विरोध की संभावना बनी हुई है। पीआरआई तथा पीएएन पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं और अगले कुछ समय तक उनकी स्थिति यथावत रहने की संभावना है। पार्टियों और उनके सदस्यों के घोटालों की जांच हो रही है, जिनके प्रचार से मतदाताओं के बीच भविष्य में भी उन्हें नुकसान पहुंचेगा।iii यह मैक्सिको में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा। जनमत संग्रह के द्वारा सामाजिक नीतियां लागू करने तथा पूर्व सरकार की नीतियों में सुधार को एक शक्तिशाली राष्ट्रपति प्रणाली के निर्माण के तौर पर देखा जा रहा है।

वेतन तथा बुजर्गों का पेंशन बढ़ाने के अलावा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत बेरोजगारी और युवाओं की शिक्षा पर जोर है। अपने छह साल के कार्यकाल में नई सरकार पेंशन व्यवस्था में सुधार और खर्च में कटौती लाकर धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश करेगी। मैक्सिको ने 1990 में निजी पेंशन व्यवस्था शुरू की थी। अभी तक चलनेवाली सार्वजनिक पेंशन योजनाओं के कारण सरकार पर खर्च का भारी भार है।[iv]

नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर युवाओं को अध्ययन तथा लाभप्रद रोजगार की ओर मोड़कर ड्रग सम्बंधी गैंग वार में वृद्धि की समस्या सुलझाना चाहते हैं। हालांकि मैक्सिको में मादक पदार्थों का सेवन अधिक नहीं होता है, लेकिन मादक पदार्थों से जुड़े गैंग वॉर और आपसी लड़ाइयों में कई लोगों की मौत हुई है। नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि अमेरिका के लिए मादक पदार्थों की लड़ाई मैक्सिको की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने अफीम और गांजा उत्पादकों के लिए क्षमादान और उत्पादक संघों के खिलाफ सेना की कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव रखा है।[v] मैक्सिको में उन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बार-बार सेना तैनात करना पड़ता है, जिसे स्थानीय पुलिस को नियंत्रित करना चाहिए। संभावना है कि सरकार पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण देगी और उन्हें ऐसे उपकरण तथा हथियार प्रदान करेगी कि वो उन परिस्थितियों को स्वयं संभाल सके। फिलहाल अमेरिका मेरिडा प्रारूप के अन्तर्गत मादक पदार्थों से जुड़े संघर्ष को रोकने के लिए मेक्सिको सरकार को आर्थिक सहायता दे रहा है। ऐसे में मैक्सिको की नई सरकार को एक ऐसी कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिसमें अपनी घरेलू नीतियां लागू करते हुए मादक पदार्थों के विरुद्ध अमेरिकी एजेंसियों का सहयोग मिलता रहे। मादक पदार्थों के गिरोहों पर कार्रवाई के कुछ क्षेत्रीय असर भी होंगे। कुछ गिरोह दूसरे देशों में स्थित हैं अथवा उनका नेटवर्क पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। सुधार के लिए नई सरकार को क्षेत्र की उन देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करना होगा, जहां मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले गिरोह सक्रिय हैं।

संभावना है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर राष्ट्रपति एनरिक पेना निएटो की सरकार द्वारा शुरु किए गए सुधारों को जारी रखेंगे। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सबके लिए शिक्षा और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर कम करने का प्रावधान है। शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी उनकी नीति है कि शिक्षा पर अधिकार सिर्फ साधन संपन्न लोगों का नहीं, बल्कि सबका है। उन्होंने देश के गरीब क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में छात्रों के लिए पोषण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव भी रखा है। साथ ही समाज के गरीब तबके के छात्रों को 2400 पेसोस (130 अमेरिकी डॉलर) की छात्रवृत्ति की व्यवस्था का प्रस्ताव है, ताकि परिवार की आर्थिक सहायता के करने हेतु छात्र पढ़ाई छोड़कर काम पर न लगें। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का भी वचन दिया है।

नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने स्पष्ट किया है कि वह शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों के लिए वर्तमान सरकार की 'श्रम अनुबंध' नीतियों में सुधार करेंगे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अध्यापक अपने काम के मूल्यांकन का विरोध नहीं करते, बल्कि उस तंत्र का विरोध करते हैं जो उनकी नौकरियां छीन सकता है। उन्होंने कहा है कि अध्यापकों को अनुबंध समाप्त किए जाने से पहले अपना प्रदर्शन सुधारने का एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया है कि इस बारे में अध्यापकों, अभिभावकों, विशेषज्ञों, शिक्षकों, नागरिक संगठनों में आम राय होनी चाहिए कि अध्यापकों के श्रम अधिकारों को प्रभावित किए बिना अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार कैसे की जाए।

वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको एक स्वायत्त संस्था बना रहेगा। वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम करेगा और भविष्य में संतुलित बजट लाने की कोशिश करते हुए टैक्स नहीं बढ़ाएगा। उसकी आर्थिक नीतियां 'गरीबों को सबसे पहले' पर आधारित होंगी और इसमें सभी नागरिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा शामिल होगी। इसमें किसानों के लिए सब्सिडी, आयातित माल पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य के साथ स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा 'स्कॉलरशिप येस, कार्टेल हिटमेन नो'[vi] नारे के अन्तर्गत युवाओं को काम सीखने के दौरान वित्तीय मदद देना और छात्रों को छात्रवत्ति देने का व्यापक कार्यक्रम शामिल है। उन्होंने पूरी सीमा पर स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जहां अमेरिकी कंपनियां कर में भारी छूट लेकर अपने दुकान स्थापित कर सकेंगी। उन्होंने अपनी आधारभूत योजनाओं के जरिए सैकड़ों-हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की है। उन्होंने व्यापक स्तर पर पेड़ लगाओ अभियान चलाने का भी निर्णय किया है, जिसमें रोजगार पाकर मैक्सिको की जनता को अमेरिका में आर्थिक अवसर तलाशने की आवश्यकता कम हो।[vii]

मीडिया समाचारों के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रपति पेना निएटो की सरकार के सुधारों की पुनर्समीक्षा की जा सकती है। नए राष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेल कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। मैक्सिको की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी अमेरिका मोविल ने दावा किया है कि वह ऐसा कर सकती है, लेकिन देश के वर्तमान नियम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। 2014 में मैक्सिको सरकार ने एक संवैधानिक सुधार किया था, जिसने दूरसंचार में सरकार की भूमिका विस्तृत कर कम्पनियों का एकाधिकार कम किया था। अमेरिका मोविल के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत की, कि इससे कंपनी उन क्षेत्रों तक पहुंचने में असमर्थ हो गई है, जहां दूरसंचार की सुविधाएं कम हैं और उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने टेलीकॉम मंत्री के रूप में जाविएर जिमनेज का चयन किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि सरकार एक स्वतंत्र नियामक के द्वारा संपूर्ण सुधारों को संशोधित नहीं करेगी, लेकिन एक ऐसा

दूसरा नियामक लाने पर विचार करेगी, ताकि कवरेज क्षेत्र की कीमत पर प्रतिद्वंद्विता प्रभावित न हो।[viii] उनके अनुसार इस क्षेत्र में सुधार की समीक्षा इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि कंपनियों की दरें कम हों, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं चुनने की स्वतंत्रता हो तथा इन नीतियों को जन समर्थन प्राप्त हो।

ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पेना निएटो के कार्यकाल में किए गए सुधारों से उनका काफी मतभेद है। नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ऊर्जा क्षेत्र में उन सुधारों के विरोधी हैं जिसने क्षेत्र को निजी संस्थाओं के लिए खोल दिया है और इस क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। ऐसा समझा जाता है कि ऊर्जा क्षेत्र से प्राप्त होने वाला राजस्व नई सरकार के सामाजिक कार्यक्रमों का वित्त पोषण कर सकता है। नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि वह उन अनुबंधों को नहीं बदलेंगे, जिन्हें पिछली सरकार ने लागू किया है। लेकिन उनके कानूनी पहलू तथा पारदर्शिता की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि वे इससे संबंधित प्रक्रियाओं का सम्मान करेंगे और अगर कोई विवाद हुआ तो विदेशी निवेशकों के हितों की गारंटी देंगे तथा विवादित मामलों को अंतरराष्ट्रीय पंचाट (ट्रिव्यूनल) में ले जाएंगे। उन सुधारों को मैक्सिकन कांग्रेस ने स्वीकृति दी है इसलिए उन्हें पलटना नए राष्ट्रपति के लिए मुश्किल होगा। ये सुधार मैक्सिको के तेल क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए हैं। सरकारी कंपनी पेट्रोलिओस मैक्सिकेनोस मैक्सिको के तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को सिर्फ अपने बूते पर पुनर्जीवित नहीं कर सकती तथा देश को सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में जारी गिरावट को रोकने के लिए विदेशी निवेश और तकनीक की आवश्यकता है, विशेषकर मैक्सिको की खाड़ी में गहरे पानी में स्थित सभी कुओं के लिए।[ix] जैसा कि नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर का वादा है कि वह स्थिर अर्थव्यवस्था प्रदान करेंगे। ऐसे में आर्थिक सुधारों से पीछे हटने पर मैक्सिको में विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है तथा उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। यह संभव है कि नए तेल तथा गैस क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए न खोले जाएं, पर सुधारों को शायद ही बदला जाए।

विदेश नीति- संयुक्त राज्य (अमेरिका) से संबंध

अमेरिका के साथ सम्बंध चुनाव अभियानों में प्रमुख मुद्दा नहीं था तथा नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने वादा किया था कि वे वाशिंगटन के साथ 'मित्रता और सहयोग' का दृष्टिकोण अपनाएंगे। मोटे तौर पर उन्हीं व्यावहारिक नीतियों को जारी रखेंगे, जो निवर्तमान पेना निएटो के प्रशासन ने चलाई हैं।[x] जहां तक नाफ्टा (एनएएफटीए) का सवाल है, तो वे उस समझौते के आलोचक रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर अमेरिका तथा कनाडा से वार्ता जारी रखेंगे। उनकी सरकार नहीं चाहेगी कि नाफ्टा को लेकर अमेरिका से उनकी वार्ता समाप्त हो, क्योंकि इसका मैक्सिको की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा तथा गरीबी से लड़ने की सरकार की क्षमता

को कम करके देखा जाएगा। मोटे तौर पर वो दोनों सरकारों के साथ वार्ता को वैसे ही आगे बढ़ाएंगे जैसे वर्तमान सरकार बढ़ा रही है। आशा है कि जो समर्थन लोपेज ओब्राडोर को मिला है, उसके चलते वो राष्ट्रपति पेना निएटो की तुलना में अधिक मजबूती से अमेरिका के साथ वार्ता जारी रख सकेंगे।

नाफ्टा के अतिरिक्त नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर सीमा सुरक्षा, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका से अमेरिका में प्रवास की समस्या और अमेरिका में मैक्सिको के गैरकानूनी प्रवासियों के निर्वासन पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि वो इन सभी मुद्दों पर अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन ये सम्बंध, सम्मान तथा आपसी सहयोग पर आधारित होना चाहिए। वाशिंगटन ने लम्बे समय से मान रखा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान, खुफिया तंत्र की सूचनाओं का आदान-प्रदान, आतंक विरोधी अभियान, मैक्सिको के रास्ते मध्य अमेरिका गमन जैसे महत्त्वपूर्ण मसलों पर मैक्सिको उसका सहयोग करेगा। इनमें से कई मुद्दों पर लोपेज ओब्राडोर प्रशासन से संपूर्ण वार्ता और समीक्षा की संभावना है। अगले राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के विचारों के अनुरूप वार्ता तथा समझौते कर सकते हैं।[xi] नए राष्ट्रपति जानते हैं कि मैक्सिको को अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक गतिशीतला को देखते हुए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको का सम्बंध मध्य अमेरिका के साथ दक्षिण अमेरिका से भी व्यापक तथा प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं।

हालांकि अमेरिका में प्रवेश करने वाले मैक्सिको प्रवासियों की संख्या में हाल के वर्षों में कमी आई है, लेकिन मध्य अमेरिका के हजारों लोग वहां की गरीबी तथा भारी हिंसा से त्रस्त होकर मैक्सिको के द्वारा अमेरिका में प्रवेश करते हैं।[xii] नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को इन मुद्दों पर बराबरी की भूमिका निभाते हुए अमेरिका से वार्ता करनी होगी। अभी ये साफ नहीं है कि नए राष्ट्रपति अमेरिका में घुसे प्रवासियों को स्वदेश लौटाने की कोशिश करेंगे या नहीं। मीडिया में आ रहे समाचारों से लग रहा है कि मैक्सिको सरकार ने अमेरिका के 'सेफ थर्ड कंट्री' समझौते का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। इस प्रस्ताव में अपने देश लौटने वाले प्रवासियों के लिए अमेरिका के बजाय मैक्सिको में पारगमन शिविर स्थापित करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत अमेरिकी सुरक्षा गार्डों को ये अधिकार होगा कि वे अमेरिका में शरण मांगने के लिए गैरकानूनी ढंग से घुसे किसी भी प्रवासी को मैक्सिको स्थित पारगमन शिविरों में पहुंचा देंगे, चाहे वे किसी भी देश के हों। अमेरिकी अधिकारियों का विश्वास है कि इस तरह के समझौते से मध्य अमेरिकी देशों के कई परिवार अमेरिका पहुंचकर शरण मांगने की कोशिश करने को लेकर हतोत्साहित होंगे। ऐसे गैरकानूनी प्रवासियों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण अमेरिकी आप्रवासी न्यायालयों में मुकदमों की भरमार हो गई है तथा इसने ऐसे लोगों को देश में

घुसने से रोकने की अमेरिकी क्षमता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।[xiii] अमेरिकी प्रशासन का विचार है कि राष्ट्रपति पेना निएटो तथा उनका प्रशासन नाफ्टा वार्ता में अनुकूल शर्तों के बदले प्रवासियों के लौटने सम्बंधी समझौते को स्वीकार करने की इच्छुक थी। लेकिन अब 1 दिसंबर को कार्यभार संभालने वाली नई सरकार से उसे ऐसी उम्मीद नहीं है।

नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने घोषणा की है कि वो मार्सेलो एबरार्ड को विदेश मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। श्री एबरार्ड सीनेट की विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष भी होंगे। श्री एबरार्ड 2006 से 2012 तक मैक्सिको शहर के मेयर रहे हैं।

कई विश्लेषकों का विचार है कि मैक्सिको तथा अमेरिका के सम्बंध नए राष्ट्रपति पर कम ही निर्भर करेंगे। इस बात पर निर्भरता अधिक होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का दक्षिणी सीमा पर क्या रुख होता है। मैक्सिको के नए राष्ट्रपति को चुनाव जीतने तथा कार्यकाल आरम्भ करने के बीच कुछ महीनों का समय मिला है। आशा है कि इस दौरान दोनों राष्ट्रपति एक ऐसा कामकाजी संबंध बनाने में सक्षम होंगे जो आगे बढ़ने की दिशा में मददगार होगा।

भारत से सम्बंध

मैक्सिको और भारत के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बंध हैं। दोनों देशों के बीच कई बातें एक समान हैं। दोनों विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। दोनों की सीमाएं ताकतवर देशों की सीमाओं से मिलती हैं। दोनों अपने क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण देश हैं। दोनों देश अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए विकसित तथा विकासशील देशों के बीच सम्बंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भारत, मैक्सिको के साथ सक्रिय रूप से मिलकर दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ अच्छे सम्बंधों की नींव रख सकता है। मैक्सिको, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिशों के अन्तर्गत इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने सम्बंधों को मजबूत बना रहा है।

मैक्सिको उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों का द्वार है। भारत के लिए यह लाभदायक है कि मैक्सिको में विनिर्माण हब बनाकर वह दोनों क्षेत्रों के बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम होगा। इसके लिए भारत को मैक्सिको के साथ अपने व्यापार के लिए साफ-सुथरे निवेश के लिए वार्ता करनी चाहिए, ताकि वे वहां पर अपनी विनिर्माण इकाईयां स्थापित कर सके। जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, उसे ऊर्जा संसाधनों के गारंटीशुदा आपूर्ति की आवश्यकता होगी। मैक्सिको तेल तथा गैस का प्रमुख उत्पादक देश है और अक्षय संसाधनों के विकास पर जोर दे रहा है। ये एक दूसरा क्षेत्र है, जहां दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं।[xiv] मैक्सिको भारत को न्यूक्लीयर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) में शामिल करने का समर्थक है। आशा है कि कुल मिलाकर भारत तथा मैक्सिको के बीच सम्बंध बेहतर होंगे। जब नए राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर संक्रमण

काल में अपनी नीतियों को विस्तार देंगे तो दोनों देशों के लिए यह उपयोगी रहेगा कि वे एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें।

निष्कर्ष

अभी यह भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी कि नए राष्ट्रपति की घरेलू तथा विदेशी नीतियां कैसी होंगी। राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर के पास अपने चुनावी वादों को नीतियों में बदलने के लिए दिसंबर तक का समय है। उन्हें अपने घरेलू एजेंडे तथा वित्तीय अनुशासन में संतुलन बिठाना होगा, जैसा वे देश की अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं। जब उन्होंने अपने घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, तो उन्हें अपने विदेश नीति के लक्ष्य की रूपरेखा भी तय करनी होगी। उन्हें अमेरिका से मैक्सिको के सम्बंधों के साथ पूरी दुनिया के साथ भी सम्बंधों का खाका तैयार करना होगा। राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर फिलहाल लाभ की स्थिति में हैं। देश में पहली बार एक अकेली पार्टी राष्ट्रपति, राजधानी तथा मैक्सिकन कांग्रेस को एक साथ नियंत्रित करेगी। इस तरह विपक्ष के विरोध का सामना करने की संभावना न के बराबर है। लेकिन उन्हें ये आश्वस्त अवश्य करना होगा कि सत्ता का दुरुपयोग न हो।

नए राष्ट्रपति से जनता की वैसी ही उम्मीदें हैं जैसी राष्ट्रपति पेना निएटो का कार्यकाल शुरू होने के प्रारंभिक दिनों में थीं। नई सरकार को लोगों ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मत दिया है तथा इन्हीं कारणों से इसे सत्ता से बाहर करने के लिए भी वोट दिया जा सकता है। इस बात का आश्वसन करना होगा कि न केवल केन्द्रीय सरकार, बल्कि राज्य तथा स्थानीय प्रशासन भी मजबूत, भ्रष्टाचार मुक्त और आपराधिक संगठनों एवं मादक पदार्थों के तस्करों से निबटने में सक्षम हो।

***

डॉ. स्तुति बनर्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में शोध अध्येता हैं
डिस्क्लेमरः आलेख में व्यक्त किए गए विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं और परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।

Endnotes

i Mr. Ricardo Anaya from the National Action Party won 22.2 percent of the votes, Mr. Jose Antonio Meade of the Institutional Revolutionary Party won 16. 4 percent of the votes and Mr. Jaime Rodríguez Calderón, an independent candidate won 5.2 percent of the votes. Figures taken from Institute for National Elections Mexico.

ii James R. Jones, “What Changes Will López Obrador Bring to Mexico?,” https://www.thedialogue.org/analysis/what-changes-will-lopez-obrador-bring-to-mexico/, Accessed on 12 July 2018.
iii Reggie Thompson, “What Will Lopez Obrador Do About Mexico's Corruption?,” https://worldview.stratfor.com/article/lopez-obrador-mexico-corruption, Accessed on 06 July 2018.
iv Reuters, “Exclusive: Pensions and Pemex to figure in Lopez Obrador's Mexico plans,” https://in.reuters.com/article/mexico-election-pensions-exclusive/exclusive-pensions-and-pemex-to-figure-in-lopez-obradors-mexico-plans-idINKBN1JS2GO,Accessed on 13 July 2018.
v William La Jeunesse, “Mexican presidential elections could deteriorate foreign relations with US,” http://www.foxnews.com/world/2018/06/30/mexican-presidential-elections-could-deteriorate-foreign-relations-with-us.html, Accessed on 06 July 2018.
vi Jo Tuckman, He was once called a “danger to Mexico.” Now he’s its next president.,” https://www.vox.com/world/2018/7/4/17532736/2018-mexico-presidential-election-winner-amlo-lopez-obrador-trump Accessed on 05 July 2018.
vii Jonah Shepp, “AMLO Isn’t Mexico’s Trump – Nor Is He Trump’s Natural Enemy,” http://nymag.com/daily/intelligencer/2018/07/amlo-not-mexico-trump.html, Accessed on 05 July 2018.
viii Julia Love, Christine Murray, “Billionaire Slim, America Movil, could profit from election of Mexican leftist,” https://in.reuters.com/article/mexico-election-slim/billionaire-slim-america-movil-could-profit-from-election-of-mexican-leftist-idINKBN1JE0B3 ,Accessed on 13 July 2018.
ix Keith Johnson, “Mexico’s Populist New President Unlikely to Derail Energy Reform,” https://foreignpolicy.com/2018/07/03/mexicos-populist-new-president-unlikely-to-derail-energy-reform-amlo-pemex-oil/,Accessed on 13 July 2018.
x Bruno Binetti, “López Obrador Will Be Mexico’s President: Now What?,” https://www.thedialogue.org/blogs/2018/07/lopez-obrador-will-be-mexicos-president-now-what/,Accessed on 12 July 2018.
xi Arturo Sarukhan, “What Mexico’s next president means for Trump” https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/07/02/lopez-obrador/?noredirect=on&utm_term=.810ba68c7602, Accessed on 13 July 2018.
xii Jo Tuckman, He was once called a “danger to Mexico.” Now he’s its next president.,” https://www.vox.com/world/2018/7/4/17532736/2018-mexico-presidential-election-winner-amlo-lopez-obrador-trump Accessed on 05 July 2018.
xiii Joshua Partlow and Nick Miroff, “U.S. and Mexico discussing a deal that could slash migration at the border,” https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-and-mexico-discussing-a-deal-that-could-slash-migration-at-the-border/2018/07/10/34e68f72-7ef2-11e8-a63f-7b5d2aba7ac5_story.html?noredirect=on&utm_term=.645b08bf1b0eAccessed on 13 July 2018.
xiv Stuti Banerjee, “Mexico’s Reform Agenda and Opportunities for India ,” https://icwa.in/pdfs/PB/2014/MexicosReformPB08092017.pdf, Accessed on 13 July 2018.